RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

No.: 29820 – 29855 Date: 05.11.2022

To,

DLSA Secretary
All Rajasthan

Sub.: Minutes of virtual meeting conducted through Video Conferencing from 02:00 PM on 02.11.2022 with regard to taking stock of preparations of upcoming NLA scheduled on 12.11.2022 regarding Bank Recovery Matters and Section 138 N.I. Act Cases.

Dear Sir,

With reference to the subject cited above, as directed, the minutes of virtual meeting conducted through Video Conferencing on 02.11.2022 are being sent enclosed herewith for sensitizing all Stake-Holders about the legal position/RBI guidelines in respect of settlement of **Bank Recovery Matters and Section 138 N.I. Act Cases** as incorporated in the minutes with the further request to make optimum use thereof in order to ensure maximum disposal of **Bank Recovery Matters and Section 138 N.I. Act Cases** in both (pending cases as well as pre-litigation matters) through amicable settlement in National Lok Adalats or other Lok Adalats.

Encl.: As above

Yours Sincerely

(Dinesh Kumar Gupta)
Member Secretary

No. 29856 – 29901 Date: 05.11.2022

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. Member Secretary, NALSA
2. Chairman, District Legal Service Authority, All Rajasthan
3. Regional Director, RBI, Jaipur
4. Chief General Manager, NABARD
5. AGM, State Level Banker's Committee
6. State Heads, Nationalized Banks, All Rajasthan
7. State Heads, Private Banks, All Rajasthan
8. State Heads, Non-Banking Financial Companies, All Rajasthan
9. Competent Authority, Apex Co-operative Bank, All Rajasthan
10. Competent Authority, Regional Rural Bank, All Rajasthan
11. Registrar Cooperative Society, Government of Rajasthan

5.11.22

Special Secretary

दिनांक 07.10.2022 को जारी किये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों के क्रम में धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों तथा बैंक ऋण वसूली के भारी मात्रा में लम्बित प्रकरणों/विद्यमान विवादों के दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होने जा रही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण के संबंध में दिनांक 02.11.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक के मीनिट्स

(Minutes of virtual meeting convened on 02.11.2022 in pursuance of detailed guidelines issued on 07.10.2022 in respect of disposal of huge pendency/existing disputes arising out of Section 138 N.I. Act cases and Bank Loan Recovery Matters through amicable settlement in upcoming NLA scheduled on 12.11.2022)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार **दिनांक 12.11.2022** को वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में रालसा द्वारा दिनांक 07.10.2022 को जारी किए गए विस्तृत दिशा–निर्देशों में इस बार जोड़े गये नवाचारों से अवगत कराने तथा उक्त विस्तृत दिशा–निर्देशों के तहत बैंक/वित्तीय संस्थानों के धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों **(मूल परिवाद/अपील/निगरानी/विविध आपराधिक याचिकाएं)** एवं बैंक रिकवरी मामलों के आपसी समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण की दिशा में कार्य–योजना तैयार कर प्रभावी कदम उठाने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म ***RSLSA-22*** एवं मोबाईल एप ***''न्याय रो साथी''*** का अधिकाधिक उपयोग करने, एकमुश्त समझौता स्कीम के तहत अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किये जाने, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने, सहकारी/ग्रामीण बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने, प्री–काउंसलिंग कैम्प के प्रभावी आयोजन, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों में आदेशिकाओं/नोटिस की प्रभावी तामील सुनिश्चित किये जाने, अधिकाधिक उपयुक्त मामले लोक अदालत में रैफर किये जाने एवं उनके निस्तारण में आने वाली कठिनाईयों, आदि बिन्दुओं ***(संलग्न एजेन्डा प्रदर्श–1)*** पर चर्चा के लिए **दिनांक 02.11.2022** को **दोपहर 02:00 बजे से** सदस्य सचिव, रालसा की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागी सम्मिलित हुए:–

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान
2. क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर
3. चीफ जनरल मैनेजर, नाबार्ड
4. सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)
5. स्टेट हैड्स, राष्ट्रीयकृत बैंक, समस्त राजस्थान
6. स्टेट हैड्स, निजी बैंक, समस्त राजस्थान
7. स्टेट हैड, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, समस्त राजस्थान
8. सक्षम प्राधिकारी, अपेक्स कॉपरेटिव बैंक, समस्त राजस्थान
9. सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्त राजस्थान
10. रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी, राजस्थान सरकार

बैठक में सभी मुददों पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के अनुसरण में (in pursuance of detailed discussion) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों की भारी पेंडेंसी के संबंध में समय–समय पर, विशेष रूप से:–

1. ***Special Leave Petition (Criminal) No.5464 of 2016, Makwana Mangaldas Tulsidas Vs. State* of *Gujarat and anr.*, *निर्णय दिनांक 05.03.2020,***
2. ***(2007) 2 Supreme Court Cases 711, ICICI Bank Ltd. Vs. Prakash Kaur,*** एवं
3. ***Civil Appeal No. 9711 of 2011, Citicorp. Maruti Finance Ltd. Vs. S.Vijayalaxmi, निर्णय दिनांक 14.11.2011*** में व्यक्त की गई भावना (concern), रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स, विशेष रूप से:–
   - **i. RBI/2004-05/95 DBOD No.LEG.BC/21/09.06.002/2004-05, August 3, 2004,**
   - **ii. LEG.BC.114/ 09.06.002/2000-01, May 2, 2001,** एवं
   - **iii. BP.BC.11/21.01.040/99-00, July 27, 2000** में जारी दिशा–निर्देशों;

तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों के मद्देनजर बैंक/वित्तीय संस्थानों के दोनों प्रकृति **(लंबित व प्री–लिटिगेशन)** के धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत एवं ऋण वसूली से संबंधित सभी मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में संबंधित हितधारकों (concerned Stake-Holders) द्वारा निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाये जाने पर सहमति बनी हैः–

A. <u>राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका (Role of RSLSA):-</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांतः–

i. ***'Special Leave Petition (Criminal) No.5464 of 2016, Makwana Mangaldas Tulsidas Vs. State of Gujarat and anr., निर्णय दिनांक 05.03.2020'***,

ii. ***'Civil Appeal No.3872 of 2012, Canara Bank Vs. G.S. Jayarama, निर्णय दिनांक 19.05.2022'***,

iii. ***'(2008) 2 SCC 660, State of Punjab & ors Vs. Jalour Singh & ors',*** एवं

iv. ***SLP Civil Appeal No. 17758/2006, United India Insurance Co. Ltd. Vs. Ajay Sinha & anr., Judgement dated 13.05.2008,*** में व्यक्त की गई भावना

तथा **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 से 22** में उपबंधित विधिक प्रावधानों एवं **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) रेगुलेशन्स, 2009** में वर्णित प्रक्रिया के साथ–साथ **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144** की भावना को दृष्टिगत रखते हुए रालसा का यह संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्व है कि वह न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों एवं पक्षकारान् के मध्य प्री–लिटिगेशन की स्टेज पर विद्यमान विवादों (विशेषकर धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों) के आपसी सुलह एवं समझाईश के माध्यम से लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में समुचित दिशा–निर्देश/स्कीम तैयार कर जारी करे एवं उनकी पालना सुनिश्चित करावें।

B. <u>रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका (Role of Reserve Bank of India):-</u>

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतः–

i. ***Civil Appeal No.5233 of 2012, Nedumpilli Finance Company Limited Vs. State of Kerala & ors., निर्णय दिनांक 10.05.2022,***

ii. ***सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम रविन्द्र एवं अन्य, (2002) 1 एस.सी.सी 367,*** एवं

iii. ***मैसर्स सरदार एसोसिएट्स व अन्य बनाम पंजाब एण्ड सिंद बैंक व अन्य, सिविल अपील नम्बर 4970–4971/2009, निर्णय दिनांक 31.07.2009***

में व्यक्त की गई कानूनी स्थिति के अनुसार **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया** अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बैंक (राष्ट्रीयकृत एवं निजी) एवं गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies) के संदर्भ में रेगुलेट्री अथॉरिटी होने के नाते ***'आम जनता के हित में तथा बैंकिग क्रिया–कलापों में गिरावट को रोकने तथा किसी बैंकिग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए वैधानिक बल रखने वाले बाध्यकारी दिशा–निर्देश' (binding directions, having statutory force, in the interst of public in general and preventing banking affairs from detoration and prejudice as also to secure the proper management of any banking company generally)*** जारी करने की अधिकारिता रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निरंतर ऐसे दिशा–निर्देश जारी करते रहना चाहिए ***(It should continue to issue such directives)***। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अवहेलना या उनकी पालना में चूक किया जाना **बैंकिंग रेगुलेशन्स एक्ट, 1949 की धारा 46(4)** के तहत दंडनीय है।

तदनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह कानूनी दायित्व है कि वह बैंकिंग गतिविधियों का सम्यक प्रचलन (due operation of banking affairs) सुनिश्चित करने

के लिए समय–समय पर तात्कालिक परिप्रेक्ष्य (contomprary scenario) को ध्यान में रखते हुए समुचित दिशा–निर्देश जारी करे तथा ऐसे दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं अवहेलना/अपालना के मामलों में समुचित दंडात्मक कानूनी कार्यवाही अमल में लावे।

2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सभी गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों का दिनांक 23.11.2013 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई ऑल इंडिया लोक अदालत में भाग लेने का आह्वान करते हुए एक **Press Release: 2013-2014/1023 November 20, 2013** भी जारी की गई है।
3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित Guidelines for Compromise Settlement of Dues of Banks and Financial Institutions through Lok Adalats जारी की गई हैं:–
    a. **RBI/2004-05/95 DBOD No.LEG.BC/21/09.06.002/2004-05, August 3, 2004,** एवं
    b. **LEG.BC.114/ 09.06.002/2000-01, May 2, 2001**
4. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय–समय पर Guidelines for recovery of dues relating to Non-Performing Assets (NPAs) of Public Sector Banks/All Commercial Banks (excluding RRBs/LABs) जारी की गई हैं। कुछ प्रमुख गाईडलाईन्स निम्न प्रकार हैं:–
    a. Master Circular No. **DBR.No.BP.BC.2/21.04.048/2015-16, dated July 1, 2015** as enclosed with RBI's letter No. RBI/2021-2022/104 DOR No.STR.REC.55/21.04.048/2021-22, dated October 1, 2021,
    b. **RBI/2013-14/601 DBS.OSMOS.No.14703/33.01.001/2013-14, dated May 22, 2014,**
    c. **DBOD.Leg.No.BC.104/09.07.007/2002-03, dated May 5, 2003,**
    d. **DBOD.No.BP.520/21.04.103/2002-03, dated October 12, 2002,** and
    e. **BP.BC.11/21.01.040/99-00 July 27, 2000** जारी की गई हैं।
5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जरिए पत्र क्रमांकः **RBI/2005-06/241 RPCD. PLNFS.BC.No.56/06.02.31/2005-06 December 27, 2005** One-Time Settlement Scheme for **Small Borrowal Accounts** and Eligibility for Fresh Loans **(जिनमें रूपये 25,000/– तक की मूल ऋण राशि बकाया रह जाती है, उनके संबंध में विशेष गाईडलाईन्स जारी की हैं)**, जिसमें **सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं** के तहत प्रदान किये जाने वाले ऋणों के मामलों में बैंकों को राज्य विशेष की परिस्थितियों के आधार पर पृथक से एकमुश्त समझौता योजना तैयार किये जाने की भी छूट दी है,
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***'सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम रविन्द्र एवं अन्य (2002) 1 एस.सी.सी 367'*** में **'कृषि उधार' (Agriculatural borrowings)** के मामलों पर भिन्न तरीके से विचार किये जाने की आवश्यकता बताते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:–

    "(6) Agricultural borrowings are to be treated on a pedestal different from others. Charging and capitalization of interest on agricultural loans cannot be permitted in India except on annual or six monthly rests depending on the rotation of crops in the area to which the agriculturist borrowers belong."
7. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित गाईडलाइन्स जारी की गई हैं:–
    a. **RBI/2017-18/4 FIDD.CO.FSD.BC.No.7/05.05.010/2017-18, dated July 3, 2017,**
    b. **RBI/2009-10/145 UDB.BPD.PCB.Cir.No.8/13.05.006/2009-10, dated September 3, 2009,** and
    c. **RBI/2004/266 RPCD.No. Plan. BC. 92/04.09.01/2004-05, dated June 24, 2004**

8. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित गाईडलाइन्स जारी की गई हैं:–
   a. **RBI/2022-2023/97 FIDD.CO.GSSD.BC.No.10/09.09.001/2022-23, dated August 1, 2022**
9. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष योग्यजन को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित गाईडलाइन्स जारी की गई हैं:–
   a. **RBI/2017-18/89 DBR.No.Leg.BC.96/09.07.005/2017-18, dated November 9, 2017**
10. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित गाईडलाइन्स जारी की गई हैं:–
    a. **RBI/2022-23/92 FIDD.GSSD.CO.BC.No.09/09.01.003/2022-23, dated July 20, 2022,** and
    b. **RPCD.PLNFS.BC.No.40/06.02.79/2000-01, dated December 12, 2000**
11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***'Small Scale Industrial Manufacturers Association Vs. Union Of India & ors, Writ Petition Civil No. 476/2020, निर्णय दिनांक 27.03.2020'*** में **कोरोना काल** के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा **नोटिफिकेशन दिनांक 27.03.2020** के जरिए घोषित Moratorium Period में Deliberate/Willfull defaulters से भिन्न बकायेदारों (defaulters) से वसूल किये जाने वाले Penal Interest/Interest on interest/Compound Interest की वसूली एवं देय हुई किस्तों के विलम्बन (deferment) के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं।
12. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आमजन पर **कोविड–19** से उत्पन्न हुए दबाव को महसूस करते हुए समय–समय पर निम्नलिखित गाईडलाईन्स जारी की हैं:–
    i. **RBI/2021-22/46 DOR.STR.REC.20/21.04.048/2021-22, dated June 4, 2021,**
    ii. **RBI/2021-22/47 DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22, dated June 4, 2021,**
    iii. **RBI/2021-22/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22, dated May 5, 2021,**
    iv. **RBI/2021-22/32 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22, dated May 5, 2021,**
    v. **RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21, dated August 6, 2020,** and
    vi. **RBI/FIDD/2018-19/64 Master Direction FIDD.CO.FSD.BC No. 9/05.10.001/2018-19, dated October 17, 2018**
13. अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को :–
    a. वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते (मूल्य सूचकांक में हुई भारी वृद्धि एवं रूपये के अवमूल्यन के मद्देनजर) हुए नई/संशोधित New/Revised Guidelines for Compromise Settlement of Dues of Banks and Financial Institutions through Lok Adalats एवं One-Time Settlement Scheme for **Small Borrowal Accounts** and Eligibility for Fresh Loans जारी करने पर विचार करना चाहिए।
    b. सभी बैंकों एवं गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों का आह्वान करने पर विचार करना चाहिए कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 में सक्रिय रूप से भाग लेवें एवं उनके द्वारा जारी की गई एकमुश्त समझौता योजना **(One-Time Settlement Scheme)** के तहत धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों एवं ऋण वसूली प्रकरणों **(लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन श्रेणी)** का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।
    c. कृषि ऋण के संबंध में समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के तहत कृषि ऋण से संबंधित धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों एवं ऋण वसूली

प्रकरणों **(लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन श्रेणी)** का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

d. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध के संबंध में समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के तहत ऋण से संबंधित धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों एवं ऋण वसूली प्रकरणों **(लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन श्रेणी)** का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

e. वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष योग्यजन को ऋण सुविधा उपलब्ध के संबंध में समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के तहत ऋण से संबंधित धारा 138 एन. आई. एक्ट से उद्भूत मामलों एवं ऋण वसूली प्रकरणों **(लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन श्रेणी)** का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

f. महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध के संबंध में समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के तहत ऋण से संबंधित धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों एवं ऋण वसूली प्रकरणों **(लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन श्रेणी)** का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

g. **कोरोना काल** के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक **RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20, March 27, 2020** के जरिए घोषित Moratorium Period में Deliberate/Willfull defaulters से भिन्न बकायेदारों (defaulters) से वसूल किये जाने वाले Penal Interest/Interest on interest/Compound Interest की वसूली एवं देय हुई किस्तों के विलम्बन (deferment) तथा अन्य समुचित राहत प्रदान करने के संबंध में दिशा–निर्देश (guidelines) जारी करने पर विचार करना चाहिए।

h. सभी बैंकों एवं गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों को रालसा द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 07.10.2022 में वर्णित निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने तथा अपालना की स्थिति में समुचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाये जाने पर भी विचार करना चाहिए।

i. रालसा द्वारा समय–समय पर सभी बैंकों एवं गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों के स्टेट हैड्स के साथ–साथ रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के प्रतिनिधिगण एवं राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधिगण के साथ आयोजित बैठकों में पारित किये गये प्रस्तावों **(मिनिट्स की प्रतियां संलग्न हैं)** की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने तथा अपालना की स्थिति में समुचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाये जाने पर भी विचार करना चाहिए।

C. <u>नाबार्ड की भूमिका (Role of NABARD):-</u>

चूंकि नाबार्ड कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास की गतिविधियों के लिए बैंक एवं वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत/वितरित किये जाने वाले ऋण/वित्तीय सुविधा की निगरानी के लिए एक वैधानिक रेगुलेट्री/सुपरवाईजरी अथॉरिटी है, ऐसे में नाबार्ड को कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास की गतिविधियों के लिए बैंक एवं वित्तीय संस्थान **(विशेषकर ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंक)** द्वारा स्वीकृत/वितरित किये जाने वाले ऋणों की वसूली के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय–समय पर जारी की गई गाईडलाइन्स एवं बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा पूर्व से जारी की हुई एकमुश्त समझौता योजना की पालना सुनिश्चित करानी चाहिए।

D. <u>राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की भूमिका (Role of State Level Banker's Committee):-</u>

चूंकि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) सभी बैंकों का एक राज्य स्तरीत स्वैच्छिक संगठन है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की

पालना के लिए सभी बैंको को राज्य स्तर पर प्रेरित करना चाहिए तथा दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराना चाहिए, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा **'छोटे उधार खातों' (Small Borrowal Accounts)** जिनमें **रूपये 25,000/–** तक की मूल ऋण राशि बकाया रह जाती है, के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांकः **RBI/2005-06/241 RPCD.PLNFS.BC.No.56/ 06.02.31/2005-06 December 27, 2005** में उल्लेखित किया गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा Master Circular No. **DBR.No.BP.BC.2/21.04.048/2015-16, dated July 1, 2015** as enclosed with RBI's letter No. RBI/2021-2022/104 DOR No.STR.REC.55/21.04.048/2021-22, dated October 1, 2021 में भी कृषि ऋण के संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) की भूमिका का उल्लेख किया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांकः **LEG.BC.114/09.06.002/2000-01 May 2, 2001** एवं **RBI/2004-05/95 DBOD No.LEG.BC/21/09.06.002/2004-05 August 3, 2004** में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) को लोक अदालत के संबंध में जारी स्कीम के प्रचार–प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) एवं जिले के लीड बैंक को लोक अदालत के तहत समझौते के लिए जारी स्कीम का जरूरी प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

E. बैंक/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान की भूमिका (Role of Banks/Non-Banking Financial Institutions):-

सभी बैंक/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान को अपनी एकमुश्त समझौता योजना का विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए यथोचित प्रचार–प्रसार करना चाहिए, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांकः **BP.BC.11/21.01.040/99-00 July 27, 2000, RBI/2005-06/131 RPCD.PLNFS. BC.No.31/ 06.02.31/ 2005-06 August 19, 2005** एवं **RBI/2005-06/153 RPCD.PLNFS. BC.No.39 / 06.02.31/ 2005-06 September 3, 2005** में निर्देशित किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***'मैसर्स सरदार एसोसिएट्स व अन्य बनाम पंजाब एण्ड सिंद बैंक व अन्य, सिविल अपील नम्बर 4970–4971/2009, निर्णय दिनांक 31.07.2009'*** में रैफर किया गया है।

सभी बैंक/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान को अपनी बैंकिंग प्रक्रिया को जनोपयोगी (people friendly) बनाना चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***(2007) 2 Supreme Court Cases 711, ICICI Bank Ltd. Vs. Prakash Kaur*** में निर्देशित किया गया है।

सभी बैंक/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान को अपनी एकमुश्त समझौता योजना (One-Time Settlement cheme) की पालना करनी चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***'मैसर्स सरदार एसोसिएट्स व अन्य बनाम पंजाब एण्ड सिंद बैंक व अन्य, सिविल अपील नम्बर 4970–4971/2009, निर्णय दिनांक 31.07.2009'*** में अभिनिर्धारित किया गया है तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय न्यायालय के ***रिट पिटिशन नंबर 22127/2021, श्री मोहन लाल पाटिदार बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2022*** के विरूद्ध बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ***एसएलपी (सिविल) नंबर 8088–8089/2022*** को ***आदेश दिनांक 13.05.2022*** द्वारा खारिज करते हुए दोहराया गया है।

F. राजस्थान सरकार की भूमिका (Role of Government of Rajasthan):-

राजस्थान सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान को रालसा द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 07.10.2022 में वर्णित निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने तथा अपालना की स्थिति में समुचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाये जाने पर भी विचार करना चाहिए।

Preparations of upcoming National Lok Adalat dated 12.11.2022

Agenda for the Virtual Meeting

Chaired by

Member Secretary, RSLSA

Date: 02.11.2022 **Time: 02:00 PM Onwards**

Participants:-

1. Secretary, District Legal Services Authority, All Rajasthan
2. Regional Director, Reserve Bank of India, Jaipur
3. Chief General Manager, NABARD
4. State Head, All Nationalized Banks, Rajasthan
5. State Head, All Private Banks, Rajasthan
6. State Head, All Non-Banking Financial Companies, Rajasthan
7. Competent Authority, All Apex Co-operative Banks, Rajasthan
8. Competent Authority, All Regional Rural Banks, Rajasthan

Agenda:-

1. **Online Pre-Counselling** (in terms of detailed guidelines dated 07.10.2022 issued by RSLSA) for amicable settlement with the borrower under prevalent **'One-Time Settlement Scheme'** floated by individual Bank/NBFC as per statutory directions/guidelines issued by RBI/NABARD from time to time, in order to explore/ensure disposal through amicable settlement of:-
   a. All the pending matters arising out of Section 138 N.I. Act
   b. All the pending matters arising out of recovery of outstanding loan amount
   c. All the pending matters filed by borrowers before Consumer Forums/Permanent Lok Adalats in respect of outstanding loan amount
2. Module of Online Pre-Counselling *qua* individual Bank/NBFC within allotted slot of time

****

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

Minutes of the Meeting

On 09.02.2022 at 04.30 PM in the Mediation Hall at RSLSA Jaipur, a meeting with regard to amicable settlement of bank recovery matters in the upcoming National Lok Adalat scheduled on 12.03.2022 was held by the RSLSA with representative of the Reserve Bank of India, Regional Office, Jaipur, Sh. Ajay Sisodia and representative of the State Level Bankers Committee, Rajasthan, Jaipur, Sh. Alok Singhal, along with representatives of other Nationalised and Private Commercial Banks.

The meeting was chaired by the Member Secretary, RSLSA, Sh. Dinesh Kumar Gupta, associated by Smt. Shalini Maharishi, Special Secretary, RSLSA.

After detailed discussion and deliberation, it is resolved that:-

1. The Reserve Bank of India, Regional Office, Jaipur may pursue with its head office to consider issuing some additional guidelines for amicable settlement of bank recovery matters in Lok Adalats in addition to the guidelines issued vide letter no. LEG.BC.114/09.06.002/2000-01 dated 02.05.2001 and RBI/2004-05/95 & LEG.BC/21/09.06.002/2004-05 dated 03.08.2004.

2. The State Level Bankers Committee, Rajasthan, Jaipur is adviced to give full page advertisement in two State wide circulated daily newspapers with a view to give publicity for promoting settlement of disputes in the bank recovery matters through upcoming Lok Adalat scheduled on 12.03.2022.

3. All the Nationalised/ Private Commercial Banks are adviced to give full publicity to the upcoming National Lok Adalat by all means, by affixing two banners/ posters/ flexes/ hoardings within the Branch premises and in rural areas, 2-3 such advertisements may be placed at prominent public places, like ATMs, Panchayat Bhawan's, Bus Stands or other similar public places.

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

Minutes of the Meeting

On 24.02.2022 at 12 Noon in the Mediation Hall at RSLSA Jaipur, a meeting with regard to the modalities of amicable settlement in loan recovery matters (Matters u/s 138 NI Act, Money Recovery Suits, Executions and Executions of Arbitration Awards etc.) in upcoming National Lok Adalat scheduled to be convened on 12.03.2022 was held by the RSLSA with representatives of the Private Commercial Banks & Financial Institutions and Learned Advocates representing such Banks & Institutions.

The meeting was chaired by the Member Secretary, RSLSA, Sh. Dinesh Kumar Gupta, associated by Ms. Poonam Durgan, Director, RSLSA and Smt. Shalini Maharishi, Special Secretary, RSLSA.

After detailed discussion and deliberation, it was resolved that:-

1. Special focus will be given on the cases wherein the loan amount is up to 02 Lakh rupees. Lists of such cases will be prepared by all the Private Banks and Financial Institutions by tomorrow in Excel Sheet (Performa will be shared through E-mail by RSLSA). After that, List will be shared with concerned DLSA and RHCLSCs.
2. Those cases will be invariably taken up for the pre-counselling in NLA between 2nd March, 2022 to 5th March, 2022 (mutually agreed dates as per the earlier meeting held on 04.02.2022).
3. The Advocates suggested that cases falling u/s 138 NI Act, in which service of accused is due, should be focused on. A mechanism for the timely service of process issued against accused in such cases should be evolved. It was suggested that a list of such cases will be shared

by each Bank/Financial Institutions with RSLSA and RSLSA will further share it with concerned DLSA with request to expedite the service of process in effective co-ordination with concern SP/SHO. It will also be explored that a cell for service of process issued against accused in sec.-138 NI Act matters is made functional at every District/Taluka level in the office of the SP or the Deputy Supdt. of Police concerned in the light of the concern about huge pendency of sec. 138 NI Act matter expressed time and again by the Hon'ble Supreme Court.

4. Directions will be issued to all the Secretaries, DLSA & Chairpersons, TLSCs that in Pre-litigation matters Banks & Financial Institutions will provide only application accompanied with duly filled notice.

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

Minutes of the Meeting dated 28.04.2022

On 28.04.2022 at 10.30 AM in the Mediation Hall at RSLSA Jaipur, a meeting with regard to amicable settlement of bank recovery matters in the upcoming National Lok Adalat scheduled on 14.05.2022 was held by the RSLSA with representative of the Reserve Bank of India, Regional Office, Jaipur, Sh. Manoj Sabharwal and representative of the State Level Bankers Committee, Rajasthan, Jaipur, Sh. R.C. Yadav, DGM & Dy. Zonal Head, Bank of Baroda, SLBC, Zonal Office, Jaipur along with state level representatives of other Nationalised and Private Commercial Banks.

The meeting was chaired by the Member Secretary, RSLSA, Sh. Dinesh Kumar Gupta assisted by Joint Secretary, RSLSA, Sh. Dheeraj Sharma.

In the meeting extensive deliberation were made on ways and means to ensure optimum settlement of cases in upcoming NLA scheduled on 14.05.2022.

After detailed discussion and deliberation, it was resolved that:-

1. Every Bank will identify the cases of those default accounts where outstanding/ Recoverable due amount is up to Rs. 02 Lac as on 31.03.2022.
2. Banks will focus on default accounts with special emphasis on cases where the defaulter belongs to SC/ST, Farmers, Differently abled and other weaker sections of society and loan were sanctioned under various Govt. schemes.
3. Bank will be free to choose any other category of default cases.
4. Individual Bank as per its own prevalent compromise scheme/ OTS scheme will be free to decide the tentative offer amount in individual cases.
5. Banks will provide the list of such cases along with the tentative offer amount, coupled with notices to the defaulter to the concerned DLSA/TLSC or RSLSA latest by 04.05.2022. The concerned DLSA/TLSC or RSLSA, as the case may be, then shall serve the notices of Pre-counselling/Door-step pre-counselling and also that of NLA stipulating the tentative offer amount to the concerned defaulter.
6. The above exercise shall be carried out as a special drive and the banks shall continue to settle the default matters in the light of RBI guidelines issued vide letter no. LEG.BC.114/09.06.002/2000-01 dated 02.05.2001 and RBI/2004-05/95 & LEG.BC/21/09.06.002/2004-05 dated 03.08.2004.

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

Minutes of the Meeting dated 14.06.2022

On 14.06.2022 at 12.30 PM, a virtual meeting through video conferencing in respect of ensuring optimum amicable settlement in pending Section 138 NI Act Cases and Bank Recovery Matters in the upcoming National Lok Adalat scheduled on 13.08.2022 was held by the RSLSA with representative of the Reserve Bank of India, Regional Office, Jaipur, Sh. Manoj Sabharwal, representative of the State Level Bankers Committee, Rajasthan, Jaipur, Sh. R. P. Vijay, DGM & Dy. Zonal Head, Bank of Baroda, SLBC, Zonal Office, Jaipur along with State Level Representatives of all Nationalised and Private Commercial Banks as well as Financial Institutions and also joined by the secretary DLSA, all Rajasthan.

The meeting was chaired by the Member Secretary, RSLSA, Sh. Dinesh Kumar Gupta assisted by Joint Secretary, RSLSA, Sh. Dheeraj Sharma.

After extensive discussion and deliberations, the consensus was emerged among Banks/Financial Institutions in respect of certain issues and accordingly it was resolved that:-

1. State Heads of all Banks/Financial Institutions shall nominate an officer in the appropriate rank as Nodal Officer Branch wise/Taluka wise/District wise/Region/Zone wise (as per requirement of the particular station) and intimate the complete contact detail of such Nodal Officer to the concerned DLSA/TLSC under intimation to the RSLSA by evening on 16.06.2022. The DLSAs/TLSCs shall coordinate and take up all the issues with such Nodal Officer, which may arise in connection with successful convening of the Special Campaign going to be launched from 27.06.2022 to 08.07.2022.
2. Concerned Secretary, DLSA in coordination with Chairman, TLSCs shall prepare separate lists of Section 138 NI Act Cases and Bank Recovery Matters (Civil Recovery Suits/Proceedings, Civil Execution and Executions of Arbitral Award) Court wise and Bank/Financial Institution wise (Branch wise); and provide the same to the Branch Manager or other authorised officer/Nodal Officer of the concerned Bank/Financial Institutions as per timeline stated in RSLSA's letter no. 13651-86 dated 10.06.2022 under intimation to the State Head of the concerned Bank/Financial Institution as well as RSLSA.
3. Concerned Bank/Financial Institution shall update such lists provided by the concerned DLSA/TLSCs in respect of complete detail of

borrower/defaulter including mobile/landline phone no. and *e-mail* ID, if available with or otherwise known to the Bank/Financial Institution concerned and shall provide the updated lists along with filled-in Notices (Revised draft of notices as provided enclosed with RSLSAs letter no. 14187-14222 with endorsement no. 14223-14225 dated 14.06.2022), specifying settlement amount to be offered for upcoming NLA dated 13.08.2022 against outstanding amount as on 31.05.2022 qua dispute existing in pending matter only, as per its own prevalent compromise Scheme/OTS Scheme to the DLSA/TLSC concerned as per timeline stated in RSLSA's letter no. 13651-86 dated 10.06.2022 under intimation to the State Head of the concerned Bank/Financial Institution as well as RSLSA.

4. Concerned Bank/Financial Institution shall share with concerned DLSA/TLSC, the calculation sheet as prepared while arriving at a settlement amount to be offered as per prevalent Compromise Scheme/OTS Scheme specifying the outstanding amount against principal sum, interest charged thereon and expenses debited in borrowers account, so that negotiations with the borrower/defaulter may be held in better and effective manner so as to ensure better results in the Pre-counselling and also to avoid any disparity between two different but similarly situated borrowers/defaulters.
5. Concerned DLSA in coordination with TLSCs shall prepare a time table for Pre-counselling *vis-à-vis* each Bank/Financial Institution specifying particular time slot for Bank/Financial Institution concerned keeping in view the number of cases going to be taken up in Pre-counselling and by considering the convenience of the Bank/Financial Institution concerned, as per time line stated in RSLSA's letter no. 13651-86 dated 10.06.2022 under intimation to the State Head of the concerned Bank/Financial Institution as well as RSLSA.
6. Bank/Financial Institution concerned shall make every endeavour to settle the pending case only and shall not insist in any manner on settlement of other disputes with the borrower/defaulter or settlement of the complete default amount/account of the borrower/defaulter, except where borrower/defaulter himself is willing to settle the complete default amount/account.
7. Concerned DLSA/TLSC shall make sure that no settlement is skipped on account of insistence of concerned Bank/Financial Institution for settlement of other dispute with the borrower/defaulter or settlement of complete default amount/account of borrower/defaulter, unless borrower/defaulter himself is willing to settle the complete default amount/account. In case of any resistance offered by the local authorised officer/nodal officer of the Bank/Financial Institution concerned, the concerned DLSA/TLSC shall instantaneously report the matter to the State Head of the Bank/Financial Institution concerned as well as to RSLSA.
8. If request is made by concerned Bank/Financial Institution, the Concerned DLSA/TLSC, shall make every endeavour to organise a separate Pre-counselling camp for concerned Bank/Financial Institution *vis-à-vis* those

cases in which settlement could be arrived at in respect of only partial default amount involved in the pending case only, but other disputes with the borrower/defaulter remained unsettled and complete default amount/account could not be settled in the current special campaign. Such separate Pre-counselling camp shall be organised on such date and time as fixed by DLSA/TLSC concerned keeping in view the convenience of the Bank/Financial Institution concerned.

9. Filled-in notices provided by Concerned Bank/Financial Institution incorporating offered settlement amount shall be served on borrower/defaulter by the Concerned DLSA/TLSC. In Section 138 NI Act Matters the notices shall be got served through Special Cell constituted by State Government recently in every District and Taluka headed by Addl. SP and Dy. SP, respectively. Whereas notices in Bank Recovery Matters (Civil Recovery Suits/Proceedings, Civil Execution and Executions of Arbitral Award) shall be got served through NAJARAT Cell/DLSA-TLSC staff/PLVs. However, all necessary support, as mutually agreed, shall be provided by concerned Bank/Financial Institution in effecting service of notices for Pre-counselling during this Special Campaign.
10. Competent Officer in Regional Office of Reserve Bank of India, Jaipur, shall write to the Central Office, Mumbai, requesting issuance of necessary Advisory/Guidelines/SOP/Instructions **at the earliest (preferably by 18.06.2022)** to State Heads of all Bank/Financial Institution to strictly comply with the resolutions taken vide these minutes in letter and spirit by referring that a request has been made by RSLSA to issue such Advisory/Guidelines/SOP/Instructions in terms of Guidelines issued by RBI/IBA (Indian Banks Association) vide letter no. LEG.BC.114/09.06.002/2000-01 dated 02.05.2001 and RBI/2004-05/95 & LEG.BC/21/09.06.002/2004-05 dated 03.08.2004 (Copy enclosed).
11. Competent Officer in State Level Bankers Committee, Jaipur (SLBC), shall also issue necessary Advisory/Guidelines/SOP/Instructions by 18.06.2022 to State Heads of all Bank/Financial Institution to strictly comply with the resolutions taken vide these minutes in letter and spirit.
12. State Head of all Banks/Financial Institution shall issue necessary Advisory/Guidelines/SOP/Instructions by 16.06.2022 to all Branch Managers/Authorised Officers Pan Rajasthan directing them to strictly abide by the resolutions taken vide these minutes in letter and spirit with further mandate to refer the matter for guidance and necessary directions to the State Office in which decision at Branch level or Regional/Zonal Office level could not be taken.
13. State Head of all Banks/Financial Institution shall incorporate in such Advisory/Guidelines/SOP/Instructions, a clause that all negotiations, which take place during Pre-counselling and One Time Settlement offers (whether written on the notice of Pre-counselling or otherwise) which are given during Pre-counselling or any stage connected therewith, clearly fall in the category of “Privileged Communication” and as such cannot be used in any legal proceedings before any legal/judicial forum (as

mandated under **Regulation 16 and 18** of the **NALSA (Lok Adalats) Regulations, 2009**, promulgated by NALSA in exercise of powers conferred by Section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987) (Copy enclosed).

14. State Heads of all Banks/Financial Institutions shall also issue pointed necessary Advisory/Guidelines/SOP/Instructions by 16.06.2022 to concerned Officers and Lawyers representing concerned Bank/Financial Institution in the Districts/Talukas to make every endeavour towards arriving at amicable settlement in execution proceedings arising out of Arbitral Award also which are pending in the Courts and shall also ensure that service of Pre-counselling notices are effected on borrowers/defaulters by providing all necessary logistic and other support required by concerned DLSA/TLSC for this purpose without fail.
15. State Head of concerned Bank/Financial Institution shall immediately intimate RSLSA, if any difficulty is faced by their Officers across Rajasthan, and RSLSA shall take up and resolve the issue instantaneously and shall also consider taking appropriate action against defaulting official of concerned DLSA/TLSC, if he is found doing any undesirable manoeuvring activity deliberately or with some ulterior motive.
16. Concerned DLSA/TLSC shall also immediately intimate RSLSA, if any instance of non-adherence of these resolutions by any official of Bank/Financial Institution or non-corporation in terms of these resolutions or non-compliance of directions issued by them in pursuance of these resolutions by some official(s) of any Bank/Financial Institution during this Campaign is noticed by it. The RSLSA shall take up and resolve the issue instantaneously and shall also recommend appropriate action against defaulting official(s) of concerned Bank/Financial Institution to State Head/Competent Authority of the Bank/Financial Institution concerned, and the State Head/Competent Authority shall apprise RSLSA about action taken in the matter as soon as possible. If it is found by RSLSA that such non-corporation or non-adherence or non-compliance has occurred on account of deliberate action/omission of the Bank/Financial Institution concerned, in such case, the matter shall also be reported to the Reserve Bank of India and other Competent Authority for appropriate action, and such Bank/Financial Institution shall also be debarred to participate in future NLAs as decided by Competent Authority in RSLSA.
17. Above exercise shall be carried out as a special drive and the Banks/Financial Institutions shall continue to settle their disputes as per existing/prevalent schemes/practices.